fa) whether Government propose to bring about some changes in the present public distribution system;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether this proposal was discussed in a Chief Ministers' Conference, held recently; and

(d) if so, the suggestions made by various Chief Ministers' and Govern ment's reaction thereto?

THE MINISTER OF FOOD AND MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV): (a) to (d) Government propose to streamline the PDS with its focus on the poor. At the conference of Chief Ministers held on 4th and 5th July, 1996 the matter was discussed. The Conference welcomed the proposal to streamline the Public Distribution System with focus on the population Below Poverty Line and issue foodgrains to them at specially subsidised prices. The details are being worked out in consultation with the State Governments.

अनुसूचित जनजाति बहुल औद्योगिक जिले

*168. **श्री जगन्नाथ सिंह:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार अनुसूचित जनजाति बहुल जिलों की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से कितने जिलों को औद्योगिक जिला घोषित किया गया है; और

(ग) उन्हें औद्योगिक जिला घोषित किये जाने के क्या कारण हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) 1991 की जनगणना के अनुसार देश में 51 ऐसे जिले हैं जिनमें 50% से अधिक आबादी अनुसूचित जनजाति की है। इन जिलों के राज्यवार नाम विवरण में दिए गए है **(नीचे देखिए)**

(ख) ऐसा कोई प्रावधान/योजना नहीं है जिसके तहत ये जिले औद्योगिक जिले घोषित किए जाएं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

1991 की जनगणना के अनुसार देश में 50% से अधिक की अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले 51 जिले हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, पांडिचेरी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की आबादी नहीं है।

आंध्र प्रदेश

1. शून्य

अरूणाचल प्रदेश

1. तवंग
2. पश्चिम कामेंग
3. पूर्वी कामेंग
4. लोअर सुबांसरी
5. अपर सुबांसरी
6. पूर्वी सियांग
7. पश्चिमी सियांग
8. तिरेप

असम

1. कार्बी अंगलोंग
2. पूर्वी कच्छार हिल्स

बिहार

1. लोहारडागा
2. गुमला
3. पश्चिमी सिंहभूम

गुजरात

1. बलसाद
2. डांगे

हिमाचल प्रदेश

1. किन्नूर
2. लाहौल स्पिति

कर्नाटक

शून्य

केरल

शून्य

मध्य प्रदेश

1. झबुआ
2. धार
3. मंडला
4. सरगुजा
5. बस्तर

महाराष्ट्र

शून्य

मणिपुर

1. सेनापति
2. तमेंगलांग
3. चौराचांदपुर
4. चांदेल
5. उखरूल

मेघालय

1. जयंतिया हिल्स
2. ईस्ट खासी हिल्स
3. वेस्ट खासी हिल्स
4. ईस्ट गारो हिल्स
5. वेस्ट गारो हिल्स

मिजोरम

1. आइजॉल
2. लंगलई
3. छिमुइपी

नागालैंड

1. कोहिमा
2. फेक
3. **तुनहेलम्बोटो**
4. **वोखा**
5. मोकोचंग
6. तैनसंग
7. मोन

उड़ीसा

1. मयूरभनी
2. कोरापुट
3. सुन्दरगढ़

राजस्थान

1. डूंगरपुर
2. बनासवाड़ा

सिक्किम

1. उत्तरी जिला

तमिलनाडु

शून्य

उत्तर प्रदेश

शून्य

पश्चिम बंगाल

शून्य

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह

1. निकोबार

दादर और नगर हवेली

1. दादर और नगर हवेली

दमन और द्वीव

शून्य

लक्षद्वीप

1. लक्षद्वीप

जम्मू और कश्मीर

जम्मू और कश्मीर में 1991 में जनगणना नहीं की गई थी।

Action taken on Recommendations of National Minorities Commission

*169. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) what are the main recommendations of the National Minorities Commission; and

(b) the action taken or proposed to be taken thereon?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA): (a) and (b) The National Commission for Minorities has recently submitted its first and second Annual Reports for the periods 1993-94 and 1994-95. The recommendations made by the Commission are being examined in consultation with the concerned Ministries/Departments. The reports will be laid before each House of Parliament alongwith the Memorandum of Action Taken on the recommendations, under Section 13 of the National Commission for Minorities Act, 1992, when this process is completed.

Loss Making Public Enterprises

*170. SHRI JAGIR SINGH DARD:
DR. SHRIKANT RAM-CHANDRA JICHKAR:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the names of top ten loss making public enterprises in the country,